साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MPHIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 18 | अंक 04 | प्रति सोमवार इंदौर, 26 अगस्त से 01 सितंबर 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

'विश्व घातक संगठन' की नई नौटंकी, मंकी बनाम मनी पाक्स

WHO के इशारे पर नाचना बंद करें विश्व के देशों की सरकारें...

WHO अमेरिका का षड्यंत्रकारी संगठन दुनिया पर कब्जा करने के लिए सरकारों को धन बांट भय फैला मोटा व्यवसाय करता है

विश्व स्वास्थ्य बनाम घातक संगठन को धन देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के साथ पूरी दुनिया में मंकी बॉक्स नाम की नई बीमारी का भय फैला अपना माल दवाइयां इंजेक्शन और टीका बेचने का नया षड़यंत्र करना शुरू कर दिया है। मंकी बॉक्स मेंउन्होंने जो फोटो दिखाएं हैं उसमें मनुष्यों के हाथ बंदर के हाथों की तरह त्वचा पर भारी मोटे-मोटे फफोले दिखाकर मटके दिखाई जा रहे हैं यह फोटो 1997 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। और ँप्द.ग्हू की साइट पर जाकर देखेंगे आप तो उसके लिए पूरा षड़यंत्रकारी 20 से ज्यादा पन्नों का विस्तृत फर्जी विवरण उपलब्ध करवा दिया गया है उसमें भी वही अंत में टीका आदि को मोटी कीमत पर बैठकर लगाने की तैयारी की जा रही है।

वैसे भी 1946 से अभी तक आपने देखा किस प्रकार से पूरी दुनिया में अमेरिकी कंपनियों ने चाहे वह ढंग से ना तो जानी पहचानी गई। ना उसके वायरस कटे हुए ना हीव्रत संख्या मेंउसके मरीज सामने आए। तो किस प्रकार से उसे बीमारी सिद्ध किया गया और नाम दिया गया। फिर भी औषधी परीक्षण का फर्जी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है स्वामी की बातें जब बीमारी ही पकड़ में नहीं आईतो दवा किस बात की और जहां तक एक बात का सवाल हैभारत के आयुर्वेद में हर प्रकार की बीमारियों की सैकड़ों वर्ष पूर्व भी व्याख्या कर दी गई जिसमें आयुर्वेद के साथ-साथ बात के ऋषियों, मुनियों और महर्षियों में जिसमें सुश्रुत चरक आर्यभट्ट जिनके आयुर्वेद, बीमारियों की व्याख्या चिकित्सा से संबंधित लिपिबद्ध शास्त्र उपलब्ध हैं व अन्य लाखों नामी बेनामी चिकित्सकों, वैद्यों नेवी हर काल हर युग में मानव जाति की बीमारियों से सुरक्षा के लिए औषधीय उच्च शिक्षा पद्धतियां विकसित की पर वे लिपिबद्ध नहीं हो पाई।

जहां तक एलोपैथी जो मात्र 100 साल से ज्यादा पुरानी नहीं परंतु यूरोपीय खासतौर से इंग्लैंड के बाद अमेरिका की कंपनियों के लिए मोटी कमाई के डकैती के साधन बन गई। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना एक वेबसाइट संवर्धनजलसा संगठन विश्व घातक संगठन का गठन कर लिया। सेवा चाकरी व अन्य माध्यम से भारत जैसे देश की जनता पर विभिन्न प्रकार के खाद्य व औषधि परीक्षण का अड्डा है सरकारों को खरीद कर यहां पर खाद्य व औषधीयों के परीक्षण के साथ-साथ भय फैला कर मोटी कमाई करता रहा है। जैसा कि अपने 1980 में एड्स का भय फैला कर कंडोम बेचने का षड़यंत्र कर स्वच्छंद योनाचार को खूब बढ़ावा देकर हमारी संयुक्त परिवार की व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया। 1990 में हेपेटाइटिस कि ऐसे लेकर ज तक की जारी की गई उसमें भी हजारों करोड़ के टीके पूरे देश में बेंचें गए। 2000 में स्वाइन फ्लू उसका भी टीका बेंचा, 2010 में चिकनगुनिया 2020 में कोरोना का तांडव आपने पूरी दुनिया में देखा इसमें लाखों करोड़ की कमाई अमेरिकी और चीनी कंपनियों की और फिर अब 4 साल बाद मंकी पाक्स का तांडव किया जा रहा है। जिसमें who.int की साइट से मंकी बॉक्स के केवल निष्कर्ष ही प्रस्तुत है

निष्कर्षः समिति ने एमपॉक्स के बहुआयामी उभार के विकास के बारे में अपनी चिंता दोहराई, जिसमें इसके इर्द-गिर्द कई अनिश्चितताएं और प्रकोप का सामना करने वाले राज्यों में एमपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने की मौजूदा क्षमताएं, या उन राज्यों में जिन्हें आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के परिणामस्वरूप ऐसा करना पड़ सकता है।

(शेष पेज 6 पर)

देश की जनता भी हिंसा महंगाई भूख बेरोजगारी से कराह रही

शांति की नौटंकी में यूक्रेन पहुंच किया पद की आड़ में मित्रों का व्यवसाय संवर्धन

जिद्दी मोटी चमड़ी के सूकर जेलिंस्की ने उल्टे ही मूढ़ को रूस से पेट्रोल आयात न करने की सलाह दी

मोदी 3 मैं हर कदम मिलती नाकामिया असफलताएं और कदम बढ़ाकर पीछे खींचने के लिए मजबूर होने की कुंठा को दूर करने के लिए अनावश्यक अनचाही जबरदस्ती का डंका बजाने के लिए की जा रही विदेश यात्राओं मेंअपनी फजीहत करवाने के साथ-साथ देश की फजीहत भी करवा रहा है यह राक्षस मोदी।

मणिपुर कश्मीर संभाल नहीं पा रहा और चले अपने 50 साल पुराने मित्र रूस को त्याग और उससे शत्रुता मोल लेने के लिए अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की यात्रा कर युध्द रुकवाने, उसने उल्टा ही ज्ञान पढ़ा दिया की रूस से तेल गैस लेना बंद कर दो। अबे चुरकट जेंलेंस्की तुम जिस रूस का हिस्सा थे। उसके पड़ोसी हो तो अमेरिका के टुकडखोर पिछलग्गू बन फिर नाटो में शामिल होने की जिद पालकर 2 साल से अपने देश व जनता की तबाही करने करवाने और देखने का शौक क्यों नहीं छोड़ते बे। हरामखोर अपनी औकात में रहना सीखो परेशानी पड़ेगी तो रूस ही काम आएगा। सूअर वह अमेरिका दुनिया की बर्बादी की वह तुम्हारी रक्षा नहीं बर्बादी करने के लिए तुमको अब हथियार उपलब्ध करवा कर अपने ही बड़े भाई से युद्ध करवा कर तुझको भी खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा है। वह कभी किसी का सगा नहीं हुआ और नाटो यूरोप के छोटे देशों के मोहल्ले के गुंडो की फौज वह सदस्य देशों को फायदा नहीं दे रहा। वहां भी अपनी सेनायें रख उन पर जासूसी करने उन देशों की सत्ता में दखलंदाजी कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने उन देशों के खर्चे पर पाल रहा है। बदले में अपने लाखों करोड़ डालर के हथियार, दवाएं, बीज और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यवसाय का अड्डा बना रखा है। मूर्ख नालायक जैलेंस्की यह बात तुझे समझ में नहीं आ रही।

(शेष पेज 2 पर)

भाजपा का जनता का शोषण करो, कर्ज लो घी पीओ

सारे विभाग खाली, न भर्तीयां न पदोन्नोतियां, न मजदूरी में वृद्धि

सत्ता बाप की जागीर नहीं, जिसे हर तरह से देश व जनता को बर्बाद करो...

भारत में पट्टे की आजादी के बाद पिछले 10 सालों में अपने मोटी कमीशन, कमाई के लिए अमेरिकी षड़यंत्रकारी संगठनों विश्व घातक संगठन, विश्व आतंकी व्यापार संगठन, और उसको धन देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच डिज्नीमोदी ने सत्ता संभालते ही सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी में जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा छोटे -मोटे उद्योग धंधे दुकानों बाजारो मंडियों को देश के हर छोटे बड़े शहर में लगभग 40 करोड लोगों को रोजगार देती थी बर्बाद कर 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया दूसरी तरफ जो नेहरू की दूरदर्शिता शिक्षक मध्य के परिणाम स्वरुप उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अंतर्गत शासकीय उपक्रमों की जो श्रृंखला खड़ी की थी। उसको भी अपने मित्रों को येन केन प्रकारेण बेंच कर जिस रेल्वे में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। रेलवे में अदानी को लाइनें, यात्री ट्रेनें मालवाहक ट्रेनें, रेलवे, स्टेशन बेंच पट्टे पर दे। लगभग 5 लाख स्थाई कर्मचारी व 5 लाख सफाई, रख-रखाव आदि के कार्यों को ठेके पर दे दिया गया। एयर इंडिया टाटा को बेंच दी गई। इसी प्रकार बैंकों, बीमा कंपनियां, तेल, बेल गेल, सेल, हाल, बीएस एन एल आदि में अनिवार्य सेवानिवृत्ति छंटनी आदि में भी लगभग 50 लाख कर्मचारियों से ज्यादा को घर बैठा दिया गया। मध्य प्रदेश में भी मूढ़ जाहिल भ्रष्ट डकैत मोदी के आने के बाद पूर्व के मुख्यमंत्री घोर धूर्त भ्रष्ट शिरोमणि शिवराज ने भी प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों को एक तरफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना लागू कर हटाया। तो दूसरी तरफ विभागों में कर्मचारियों की मृत्यु सेवानिवृत्ति के कारण अधिकांश विभागों में 10 से 30% स्टाफ रह गया।

(शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

आपराधिक मानसिकता की सत्ता व उसकी गंदी राजनीति

वर्तमान में बैठे आपराधिक मोदी व उसके गिरोह के अपराधी मंत्रियों की सरकार अपनी नाकामियों लूट डकैती को छुपाने जाति संघर्ष फैलाने इसके नेताओं द्वारा स्वयं अपराध करने अपराधियों को संरक्षण देने के कारण इसकी चारों तरफ न केवल देश में वरन दुनिया में भी थू थू होने की बावजूद भी समाचार पत्रों टीवी न्यूज़ चैनल मिडिया को जनधन से अरबों रू के विज्ञापन बांट मुंह बंद कर अपनी फर्जी प्रशंसा का तांडव किया जाता है। जबकि सोशल साइट्स परजनता उसके खिलाफ सोशल साइट्स पर 2-5% सच पीड़ितप्रस्तुत कर ही देते हैं। पर बेर्शम निकंमों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा उस हर बलात्कारी-यौन उत्पीड़क के पक्ष में खड़ी होती है, जो उसे राजनीतिक लाभ पहुंचा सके; वह तभी बलात्कर-बलात्कारी के विरोध में खड़ी होती है, जब उसे राजनीतिक लाभ हो।

इसके तथ्य निम्न हैं-

1) भाजपा पूरे समय ब्रजभूषण शरण के साथ खड़ी रही, महिला पहलवान चिल्लाती-चिखती रहीं कि यह यौन उत्पीड़क है पुलिस ने अपनी चार्ज शीट में कहा है कि ब्रजभूषण शरण ने यौन उत्पीड़न किया, इसके प्रमाण हैं। भाजपा पाखंड करते हुए उनकी जगह उनके बेटे लोकसभा का टिकट दिया, क्योंकि कैसरगंज से ब्रजभूषण चुनाव जीत सकते हैं, चाहे बेटे के लिए ही सही।

2) राम रहीम को बलात्कार और हत्या के जुर्म में सजा हो चुकी है, वह बार-बार भाजपा की सरकार की मदद से पैरोल पर बाहर आता रहता है, जेल उसके लिए ससुराल बन चुकी है। क्योंकि राम रहीम भाजपा को चुनावी मदद पहुंचा रहा है।

3) बलात्कारी सेंगर को अंतिम समय तक भाजपा बचाती रही, उसकी हर तरह से मदद करती रही, क्योंकि वह चुनाव जीत और जिता सकता था।

4) चिन्यमयानंद को तो खुल्लम-खुल्ला यौन उत्पीड़न का वीडियो आने के बाद क्लीनचिट दे दी गई।

5) मणिपुर में कूकी महिलाओं के सामूहिक बलात्कारियों को भाजपा की वीरेन सिंह सरकार डंके की चोट पर बचाया और उनका पक्ष लिया। अमित शाह और मोदी उनकी पीठ थपथपाते रहे, वीरेने सिंह बलात्कारियों के साथ थे।

6) हाथरस की दलित लड़कियों के बलात्कारियों को बचाने की हर कोशिश तथाकथित सन्यासी योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा के अन्य नेताओं ने किया, क्योंकि बलात्कारी भाजपा के मुखर वोट (ठाकुर समुदाय) के थे।

सबसे पहले भाजपा मुस्लिम महिलाओं के सामूहिक बलात्कारियों के पक्ष में खुल्लम-खुल्ला खड़ी हुई, क्योंकि बलात्कारी हिंदू थे। बिलकिस बानो और कठुआ की बच्ची के सामूहिक बलात्कारियों के साथ जुलूस और गाजे-बाजे के साथ भाजपा खड़ी हुई है। पहले बलात्कारियों का पक्ष हिंदू के नाम पर लिया गया, क्योंकि मुसलमानों के प्रति असीम घृणा के चलते एक बड़ी संख्या में इससे हिंदू वोटों को अपने पक्ष में किया जा सकता था। फिर कहीं ठाकुर के नाम पर और कभी अन्य नाम पर। जब आप एक बार किसी भी तर्क के आधार पर बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं, अपने समर्थकों को बलात्कारी के साथ खड़े होने के लिए तैयार करते हैं, फिर आप हर तरह के बलात्कारी के साथ खड़े होने लगते हैं, यदि वह किसी तरह आपके फायदे का हो। आपको चुनाव जिता सके, आपकी सरकार बनाने में मदद कर सके और प्रधानमंत्री बना सके। जैसे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ खड़े होकर, प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत कर पाक-साफ हो जाते हैं, वैसे ही बलात्कारी-यौन उत्पीड़क भी भाजपा के साथ खड़े होकर, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत कर मासूम और निर्दोष हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति की तथाकथित संरक्षक आरएसएस चुप्पी साथ लेता है या गुपचुप या खुले रूप में बलात्कारियों को बचाने में भाजपा के साथ खड़ा हो जाता है, आखिर उसे हिंदू राष्ट्र जो बनाना है। हिंदी राष्ट्र के लिए बलात्कारियों-यौन उत्पीड़कों और भ्रष्टाचारियों का सौ खून माफ किया जा सकता है। कोलकाता बलात्कर कांड के विरोध में सिर्फ राजनीतिक लाभ के खड़ी हुई है।

शांति की नौटंकी में यूक्रेन पहुंच किया पद की आड़ में मित्रों का व्यवसाय संवर्धन

पेज 1 का शेष

भारत के जाहिल वाचाल मोदी को बुलाकर तुम यह उम्मीद कर रहे हो। कि तुम्हारा युद्ध रुकवा देगा मूर्ख अपने देश में 10 साल में अपने देश के मानव निर्मित को प्राकृतिक संसाधनों को बेंचकर मोटा कमीशन हजम करने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियांचुने 10-20 पूंजीपति मित्रों के लिए 140 करोड़ की आबादी को सत्ता में बैठते ही साथ सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी में सिवाय बर्बादी के अलावा उसने कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा छोटे-मोटे उद्योग दुकानें बाजार मंडिया जहां लगभग 20 करोड लोगों को रोजगार मिला हुआ था खत्म कर 20 करोड लोगों से देश में 100 करोड़ गरीबपैदा कर 5 सालों से रु.1 किलो का गेहूं और रु. 2 किलो का चावल खिला गुलाम भिखारी बेरोजगार बना पल रहा है। अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए मणिपुर की जमीन हड़पने स्वयं उसकी ही पार्टी दंगे करवा करएक तरफ औरतों का बलात्कार कर रही है तो दूसरी तरफ हिंसा आगजनी मेंपूरे मणिपुर की बर्बादी का कारणबन लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। तो तुम्हारा खाक भला कर देगा।

जहां तक रूस से पेट्रोल लेने का सवाल है। तो वह हरामखोर 125 करोड़ की आबादी की आवश्यकतायें पूरा करना देश चलाना और अपने देश की जनता के हितों को संभालने के लिये तुम जैसे जिद्दी सूअर के हित साधने के लिए नहीं त्यागी जा सकती। जब तुम अपनी छोटी सी जिद नहीं त्याग सकते तो हमारे 50 साल पुराने रूस जैसे मित्र जिसने हमेशा अमेरिकी राक्षसों के षड़यंत्रो के विरुद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध में भी 71 में उसी ने सहयोग किया था। फिर अमेरिका दुनिया में कब किसके सगे हुए। संकर प्रजाति अमेरिका ने कब भारत के हित में कुछ अच्छा और बेहतर किया केवल अपना व अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल बेचने अपनी शर्तें मनवाने देश को लूटने देश की जनसंख्या को बेरोजगार करने के अलावा पिछले 75 साल में भारत के साथ तुमने क्या किया? और अभी जो तुम तारीफ कर रहे हो उस मोदी सै अपना हित साधने रूस से दोस्ती खत्म करवाने तुम ही आखिर जेंलिस्की से खुद क्यों नहीं बोलते की भाई नाटो में शामिल होने से मना कर दे या हम तुम्हें नाटो में शामिल नहीं करेंगे यदि यह छोटी सी बात 2 साल पहले ही बोल दी जाती।तो कोई युद्ध ही नहीं होता और अभी भी बोल दोगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। परंतु तुम्हें अपना कबाड़ा हथियार बेचने हैं वहां जासूसी के अड्डे स्थापित करने हैं। दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाने लूटने बर्बाद करने हथियार बेचने माल दबाए टीका बेचने दुनिया को गुलाम बनाने के षड्यंत्र में, रूस जो हमारा पिछले 70 साल से प्रतिद्वंदी है? तुम्हारी हर चाल को नाकाम करने तुम्हारी दादागिरी को कमजोर करने के कारण तुम उसको चारों तरफ से घेरना व बर्बाद करना चाहते हो। इसलिए तुम यूक्रेन को मोहरा बना साथ मिलकर वहां पर तबाही का तांडव करवा रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि युक्रेन बर्बाद हो चुका है। रूस बर्बाद हो रहा है। तुम तो मौत के हथियारों के सौदागर हो। कोई भी बर्बाद हो अपना माल बिकना चाहिए अपनी दादागिरी चलना चाहिए उसके लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। जेलेंस्की व मोदी जैसे अक्ल के पैदल ही तो तुम्हारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटी कमाई वह विश्व पर अपनी दादागिरी चलाने के साधन हैं।

बदलेगा वर्ल्ड-ऑर्डर या शुरू होगा कोल्ड वॉरष्ठ PM मोदी के यूक्रेन दौरे का क्या होगा ग्लोबल परिणाम?

पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर गए हैं. साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब यूक्रेन की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा नहीं किया था. अब सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के दखल के बाद करीब 30 महीने से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध थम जाएगा या फिर दुनिया 1991 से पहले चल रहे कोल्ड वॉर के युग में पहुंच जाएगी?

दुनिया की सबसे भीषण रणभूमि बन चुके यूक्रेन की राजधानी में जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरी दुनिया को महाविनाशकारी युद्ध से बचाने की गंभीर कोशिश की है. महायुद्ध को टालने और शांति लाने के लिए, कीव के मैरिंस्की पैलेस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जेलेस्की के बीच 3 घंटे तक गंभीर बात हुई. पीएम मोदी के इस शांति प्रयास पर यूनाइटेड नेशन ने भी भरोसा जाहिर किया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोदी युद्धविराम कराएंगे तो इसका ग्लोबल परिणाम क्या होगा?

30 महीने से बारूदी धमाके झेल रही यूक्रेन की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया. साफ साफ कहा कि जंग में भारत तटस्थ नहीं है क्योंकि हम शांति के पक्ष में हैं. अब बिना एक भी मिनट गंवाए जेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए. समाधान का रास्ता बातचीत और कूटनीति से निकलता है. हमें बिना समय गंवाए उस दिशा में बढ़ना चाहिए. बच्चों की शहादत की जगह को देखकर मेरा मन भरा हुआ है. मैं विशेष रूप से आपसे शांति को लेकर चर्चा करना चाहता हूं. मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिया भूमिका निभाने के लिए तैयार है. अगर इसमें कोई योगदान हो सकता है तो एक मित्र के रूप में जरूर करना चाहूंगा.

पीएम मोदी की सब सुनते

इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही वो अकेले शख्स हैं, जिनकी बातों को बाइडेन भी गंभीरता से सुनते हैं और पुतिन भी. पीएम मोदी का वाशिंगटन भी सम्मान करता है और मॉस्को भी. प्रधानमंत्री मोदी को कीव में भी वैसा ही सम्मान मिला. प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के साथ उनके आधिकारिक निवास मरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक गंभीर मंथन किया और जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया कि भारत इस क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर और हर मुमकिन कोशिश करेगा. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से यूक्रेन में छिड़ी जंग खत्म करने में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर गए हैं. साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब यूक्रेन की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा नहीं किया था. अब सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के दखल के बाद करीब 30 महीने से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध थम जाएगा या फिर दुनिया 1991 से पहले चल रहे कोल्ड वॉर के युग में पहुंच जाएगी?

बदलेगा वर्ल्ड-ऑर्डर या शुरू होगा कोल्ड वॉर

ये डर इसलिए है क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध के खत्म होने के बाद भी रूस और अमेरिका के बीच की जंग खत्म नहीं हुई थी. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दो साल बाद 1947 में शुरू रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जो 1991 में सोवियत संघ के पतन तक चला. इस युद्ध को कोल्ड वॉर कहा गया क्योंकि इसमें रूस और अमेरिका जैसी दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे तौर पर कोई युद्ध नहीं हुआ लेकिन उनके साथ खड़े कई देश इस जंग में बर्बाद हो गए. क्या रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? ऐसा ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों के साथ बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं. बीते कुछ महीनों में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में बाइडेन के साथ बात कर चुके हैं. मॉस्को के राष्ट्रपति आवास में पुतिन से मीटिंग कर चुके हैं और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मैरिंस्की पैलेस में जेलेंस्की के साथ शांति का स्थाई रास्ता निकाल रहे हैं.

युद्ध को सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है- जेलेंस्की

पीएम मोदी के कीव दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा. मुझे लगता है कि भारत ने ये पहचानना शुरू कर दिया है कि ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये एक आदमी का असली युद्ध है और उसका नाम पुतिन है पूरे देश के खिलाफ जिसका नाम यूक्रेन है. आप एक बड़ा देश हैं. आपके पास एक बड़ा प्रभाव है और आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर रख सकते हैं यानी अब यूएन को भी भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध को विनाशकारी महायुद्ध बनने से सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है.

ढाई साल के युद्ध में यूक्रेन को कितना नुकसान

यूक्रेनी वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से 22 अगस्त 2024 तक यूक्रेन पर हमले के बाद से 6,03,010 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं. यूक्रेन ने पिछले ढाई साल में रूस के 8,522 टैंक्स, 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम, 367 हवाई जहाज, 328 हेलिकॉप्टर, 13,902 ड्रोन्स, 28 जहाज और 2 सबमरीन बर्बाद किए हैं. यूक्रेन सरकार ने युद्ध में यूक्रेन को हुए नुकसान के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मानता है कि इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के 70,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और घायल सैनिकों की संख्या 1,20,000 से ज्यादा है.

इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए हैं. ये आंकड़ा यूक्रेन की कुल आबादी के एक तिहाई से भी ज्यादा है. इस युद्ध में अब यूक्रेन के 37% घर तबाह हो चुके हैं. इस युद्ध में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से 500 बिलियन यानी 50000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है.

इस तबाही को रोकने की गंभीर कोशिश करने के लिए कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेस्की से साफ साफ कहा कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अगर व्यक्तिगत तौर भी इसके लिए वो कोई योगदान दे सकें तो जेलेंस्की और पुतिन दोनों के मित्र की तरह वो ये जरूर करेंगे.

सीजीएसटी निरीक्षक व अधिकारी छापेमारी व वाहन पकड़ जांच करते हैं

जीएसटी कानून केंद्र व राज्य कर वसूली के लिए एक ही

राज्य के जीएसटी विभाग में आयुक्त, छापेमारी व वाहन पकड़ कर कर चोरी रोकने आदेश ही नहीं देते

मध्य प्रदेश राज्य जीएसटी मुख्यालय इंदौर में होने के बाद में भी बेशक यह व्यावसायिक राजधानी है यहां बड़े-बड़े व्यावसायिक व औद्योगिक संगठन दो नंबर का काम करना उनकी मजबूरी है। और उन व्यावसायिक औद्योगिक संगठनों द्वारा धन में से सीधा ही मोटा धन आयुक्त और मंत्री को पहुंचा कर राज्य के स्तर पर के साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अडानी अंबानी जैसा की सन 2006 में लिख रहा था कि वे सीधे ही दिल्ली में बैठे मंत्रियों और प्रधानमंत्री को साथ कर करो की छूट लेकर छोटे व्यापारियों उद्योग ऑन दुकानदारों को खत्म करने का संयंत्र करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ की दिल्ली के स्तर पर अडानी अंबानी टाटा बिरला आईटीसी युनिलीवर जैसे बड़े उद्योगपति व देशी व वॉलमार्ट अमेजॉन व अन्य अनेकों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीधे ही मोटा धन पहुंचा कर करो में छूट ले लेंगे और वहीं वर्तमान में हो रहा है। बेशक उसका कुछ हिस्सा सीधे ही भोपाल स्थित राजधानी में मंत्री मुख्यमंत्री प्रधान सचिव और आयुक्त को बांटकर छापेमारी और धारा 68, 71 के अंतर्गत वाहन पकड़ने कर चोरी रोकने के इसलिए जान बूझकर वाहन जांच करने के आदेश नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार का सीजीएसटी विभाग के अंतर्गत मप्र में बैठे कमिश्नर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर अपने उपायुक्तों सहायक आयुक्तो से लेकर निरीक्षकों तक सबको धारा 68, 71 में माल पर कर चोरी रोकने के लिए वाहन पकड़ने जांच करने के साथ मोटी वसूली कर कर वसूलीकरने और दंड रोपित करके सरकारी खजाने में भी जमा करवाते हैं।

माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में धारा 68 और 71 में रास्तों में वाहनों को पकड़कर जांच करने के अधिकार देने की शक्ति यथार्थ में संयुक्त आयुक्तों के पास में हैं। परंतु जब हरामखोर राज्य शासन में बैठे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सीधे ही महीना देकर मुंह बंद करके रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वे भूखे कमीशनखोर श्वान बेचारे कैसे नीचे अपने अधिकारियों निरीक्षकों कर्मचारियों को कैसे शक्तियां विकसित करकर चोरी रोकने केलिए छापा मारने और वहां पड़कर जांच करने के अधिकारों का वितरण करेंगे जबकि आप देखते हैं कि जितनी भी यात्री बसें जो लगभग संख्या में 5000 से ज्यादा जो अंतरराज्यीय मार्गो पर जो प्रदेश के लगभग 40 शहरों से मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, धूलिया, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जो प्रतिदिन दूसरे प्रदेशों में प्रतिदिन लगभग 2000 करोड रुपए से ज्यादा का माल लेकर जाती आती है। और खुले में कर चोरी करती हैं। जिनको वर्तमान आयुक्त धनराजू कर चोरी करने के लिए वाहन पकड़ने के आदेश न देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं।

दूसरी तरफ अफीम गोदाम की 5 एकड़ से ज्यादा जमीन जो आरएनटी मार्ग पर छावनी में है। आजादी के पूर्वी है जमीन अंग्रेजों के पास थी जो आजादी के बाद से 75 सालों से शासन के पास है। और सुखाधिकार अधिनियम 1962 में जिसका कब्जा 20 साल या उससे ज्यादा समय सेस्वतंत्र रूप से जिसके पास होता है वह उसका मालिक हो जाता है।

दूसरी तरफ इंदौर में आने वाला हर कलेक्टर कमिश्नर जो भूमिया कॉलोनी माफिया को संरक्षण दाता होता हैअपनी मोटी कमाई के लिए बसी बसाई कॉलोनी कोअनु को प्रकार के बहाने लेकर तोड़फोड़ कर देता है परंतु अफीम गोदाम की जमीन से सरकार के पास होने के बाद भी उसे पर वह अपना बहुमंजिला भवन बनाकर अपना कार्यालय बनाना नहीं चाहता। क्योंकि चेतक चेंबर के में वह वर्तमान में 25 लख रुपए से ज्यादा का हर महीने 20% कमीशन पर किराया चुका रहा हैऔर हाल ही में पांच नंबर वृत का जो भवन था उसका जानबूझकर उचित ढंग से रख रखाव ना कर उसे खंडहर घोषित करश्री वर्जन परिसर में लाखों रुपए महीने परतीसरी मंजिल पर वृत्त क्रमांक 5 को स्थानांतरित करने के साथ पूर्व से वहां चल रहे संयुक्त आयुक्त वृहत कर इकाई और अंकेक्षण कार्यालय वहां पूर्व से ही चल रहे हैं। उसका भी 12 साल से अधिक समय से लाखों रुपए में किराया मोटे 25% कमीशन पर चुकाया जा रहा है।

चेतक चेंबर में भी कार्यालय को स्थानांतरित किये 22 साल से ज्यादा हो गया। जबकि 1 लाख वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन पर मिसाल कार्यालय बनाया जा सकता था। फिर भी पर्याप्त पार्किंग भी रहती और पकड़े गए वहां को खड़ा करने का भी पर्याप्त स्थान मिलता। राजेश की कलेक्टर कमिश्नर आसानी से उसे जमीन को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी सुखाधिकार अधिनियम 1962 के अंतर्गतअपना कब्जा होने के कारणशासन के नाम अंकित करभवन बनाने के व्यवधान दूर कर सकते थे। परंतु बहुत दूर करने की अपेक्षा जानबूझकर उस मामले को उल्झाये रखने और तृतीय पक्ष को से मोटा पैसा मिलने की उम्मीद पाले बैठे हैं। जबकि यदि अभी भी भवन बना दिया जाए। तो विभागीय मुख्यालय के साथ सारे वृत, उपायुक्त अपील ऑडिट एलटीयु आदि कार्यालय वहां खोले जा सकते हैं। पर जब हरामखोरों की दाड़ में किराए में भी 20 से 30% कमीशन का खून लगा हो। तो बहानों की कमी कहां हो सकती है? उल्टे ही जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर परिसर के अंतर्गत अपनी दुकान में डाल रखी है। और स्थाई निवास बना रखा है। जिसे शासन शक्ति संपन्न होने के बाद में भीखाली नहीं करवा पा रहादूसरी तरफ राजस्व व नगर निगम के कलेक्टर कमिश्नर अपनी मोटी कमाई करने के लिए विभिन्न वाहनों के आधार पर वर्षो से बसी बसाई कालोनियां बहुमंजिला अपनी उचित महीना वसूली के अभाव में, शासन की, नजूल, नदी, नालों, ग्रीन बेल्ट की अवैध, वक्फ की या अन्य कई बहानों, नियम कानून के आधार पर तोड़फोड़ कर नष्ट कर देता है। तो आखिर और राजस्व व नगर निगम के अधिकारियों का यह दोगलापन दोहरापन क्यों?

श्रीवर्धन कांप्लेक्स आरएनटी मार्ग पर चल रहा एल टी यूनिट में कोई खास जिम्मेदारी न होने के कारण अधिकांश स्टाफ 12:00 बजे आता है और 4:00 बजे चला जाता है वहां से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कई अधिकारी कर्मचारी 16 अगस्त को बिना छुट्टी का आवेदन दिए गायब थे जिसमें संयुक्त संचालक भी शामिल है। क्योंकि वहां पर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है दूसरी तरफ ऑडिट में भी जो अधिकारी पदस्थ हैं। उसमें से एक नितिन जैन सहायक आयुक्त से बातचीत करने पर वह भड़क गया और बदतमीजी के साथ बोले आप ऑफिस में घुसने वाले और पूछताछ करने वाले होते कौन हैं?

तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी को विशेष आमजन से बात करने का तमीज ना हो, ऐसे अधिकारियों को भिंड मुरैना बालाघाट सतना भेजा जाना चाहिये। पूरे विभाग में वर्षो से कर्मचारी अधिकारी एक ही पद पर एक ही व्रत व जिले में वर्षो तक कुंडली जमाई बैठे रहते हैं उनका स्थानांतरण जो 3 वर्ष में होना चाहिए 10-10 वर्षों तक नहीं होता। और जहां तकहर कर्मचारी अधिकारी का 3 वर्ष के बाद पदोन्नति होनी चाहिएउसे पर तो यह भ्रष्ट निगम में भूखेड़ा जन पार्टी की सरकार कुंडली मारे बैठी हुई है। जैसे सत्ता नियम कानून व्यवस्थाएं मोदी के प्रधानमंत्री या मोहन यादव के मुख्यमंत्री बन जाने पर पूरी इनके बाप की जागीर हो गई। व सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को पदोन्नति देने से उनका वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं सब इनकी जेब से भुगतान किया जा रहा हो। जो इनको पदोन्नतियां नहीं दी रही और भर्तीयां नहीं की जा रही।

वैसे भी पूरा वाणिज्य कर विभाग में चूंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर मुख्यालय से लेकर नीचे वृत्त कार्यालयों तक कोई भी भ्रष्ट अपने भ्रष्टाचार जलसा दिया छुपाने अधिनियम की धारा 2 ज 4 के अंतर्गत नाथू यूआरएल बताता है और ना ही वह जानकारी सीडी में दी जाती है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर विभागीय आयुक्त प्रधान सचिव मंत्री मुख्यमंत्री तक जो कानून से कानून का पालन करने के लिये पदस्थ किए जाते हैं। जिन्हें जनता के धन से वेतन मिलता है। परंतु सूचना के अधिकार का भारी मन खोलो उड़ाते हैं। आखिर मुख्यालय में बैठे लोक सूचना अधिकारी जिसे उपायुक्त स्तर का और अपीलीय अपर आयुक्त अधिकारी स्तर का होना चाहिये। जिसे जीएसटी कानून लागू होने पर एक पद की वृद्धि कर देने से उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाना चाहिए था। जैसा की धारा 19(5) में दिया हुआ है।

उक्त कानून में शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और जनता के किसी व्यक्ति के आवेदन देने पर उसे चाही गई जानकारी ईमानदार और सार्थक प्रयासों से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी पर इसके विपरीत सभी शासकीय विभागों में आवेदन देने पर सूचनाओं ना देने का हर कदम सुरेंद्र किया जाता है जिसमें एक वाणिज्य कर विभाग भी है जिसे सुधारा जाना चाहिए।

उच्च पदों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों व नेताओं की औलादों की सीधी भर्तियां क्यों?

सत्ता में सीधे प्रवेश करवा, हित चिंतन व सत्ता सुख भोग

पूर्व की सारी नियुक्तियां रद्द की जाएं। सीधे उच्च पदों पर बैठ कौन-कौन से निर्णय लिए समीक्षा की जानी चाहिए। जन व राष्ट्र हितों के विरुद्ध सारे आदेश व निर्णय भी तत्काल प्रभाव से खत्म करो।

देश की सत्ता पर सन 2014 में छल बल दल और झूठे वादों से जनता को भ्रमित कर कब्जा करने के बाद भुखेरा जन पार्टी की सरकार और उसकी पितृ संस्था और राष्ट्रीय शोषण संघ मैं मिलकर 1930 के एजेंडा जिसमें पूंजी पतियों के इशारे पर नाच चंद पूंजी पतियों को सारे देश की सार्वजनिक उपक्रमों संपत्तियों को कबाड़े के भाव बेंच, वित्तीय संस्थानों को खोखला कर बर्बाद करने का षड्यंत्र 10 साल में जनता ने बहुत तरीके से समझ लिया।

जैसा कि उस जाहिल आपराधिक मानसिकता के मोदी व शाह के गिरोह के मंत्रिमंडल में बैठे आपराधिक प्रकृति के मंत्रियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को नष्ट कर देश को अपनी तरीके से अपने तरीके से हांकने नोचने चलाने के लिए संविधान को बदलने अपने कानून थोपने काजू षड्यंत्र किया था यदि तीसरे कार्यकाल में भीपूरे बहुमत के साथ सत्ता मिल जाती तो पूरी तरह से जनता को भेड़ बकरियों को तरह गुलाम बनाकर नचाने, लूटने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने का षड्यंत्र तैयार था।

पहले और दूसरे कार्यकाल में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा धन लेकर उनके हितों की संरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री व अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जिसमें आपने देखा वित्त मंत्रालय में भारतीय रिजर्व बैंक में अंबानी के जीजा उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया था। और उसके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए पुराने 1000 व 500 के नोटों को आतंकवाद की आर्थिक स्थिति को तोड़ने कमजोर करने के लिए रद्द कर 500 व रु 2000 के नए छापने का षड्यंत्र किया। उसे प्रिंस की आड़ में जो 65 साल में कांग्रेस ने मात्र 17 लाख करोड रुपए की पत्र मुद्रा चलन में डाली थी। कैशलेस और ऑनलाइन पेमेंट करने की व्यवस्था करने के बाद में भी नए नोट हड़पने, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करने के लिए करीबन 34 लाख करोड रुपए के नए नोट चलन में डालने उसका सदुपयोग स्टॉक मार्केट में करने के अपने मित्रों के शेयरों की कीमत दोगुना कर 40 हजार के सूचकांक को 80000 पर ले आया गया। सूचना के अधिकार में रिजर्व बैंक में स्वीकार किया की 88000 रू 2000 के नोट बेंगलुरु से विभिन्न बैंकों की शाखाओं को पहुंचाते समय गायब कर दिए गए। इसके बारे में देश के किसी भी थाने में कोई एफआइआर वित्त मंत्रालय व उसके संस्थानों ने नहीं करवाई। अर्थात 1,76,000 करोड़ की नगदी व अधिक छापी गई 17 लाख करोड रु की नगदी ने भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन ने महंगाई को दुगना कर दिया गया। जबकि आम आदमी की कमाई और प्रति व्यक्ति आय घटती चली गई ताकि लोगों को गुलामों की तरह मजदूरी करवा कर शोषण किया जा सके। पूर्व और वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को भी इसी इसी योजना के अंतर्गत आइएस बना दिया गया। पुनः तीसरे कार्यकाल में जब सीधे ही उच्च पदों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के साधन में प्रतिनिधियों की व नेताओं की औलादे को सीधे पदस्थ करने का षड्यंत्र करने के लिए सीधे ही विज्ञापन निकाला गया, तो पूरे देश में विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ सत्ता में शामिल अन्य राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन खड़ा कर दिया।

यूपीएससी ने कल प्राइवेट सेक्टर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा पीएसयू कर्मचारियों के बीच से संयुक्त सचिव, निदेशक और डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के 45 पदों पर लैटरल प्रवेश के लिए आवेदन मांगा है। ये सारे पद 17 सितंबर तक 24 केंद्रीय मंत्रालयों में भरे जाने हैं।संयुक्त सचिव की कुल 10 रिक्तियों को डिजिटल इकोनामी, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और वित्तमंत्रालय में निवेश तथा गृहमंत्रालय के एनडीएमए समेत कई मंत्रालयों में भरा जाना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इन पदों के लिए योग्य नहीं है। ऐसा रिक्तियों के विज्ञापन में कहा गया है। संयुक्त सचिव के लिए आवेदन करने की जो शर्तें मांगी गयी हैं उनमें कम से कम 15 साल के अनुभव की जरूरत है। और उस शख्स की उम्र 40 से 55 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त सचिव के लिए कुल सैलरी 2.32 लाख रुपये प्रति महीने होगी। जबकि निदेशक और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए किसी अभ्यर्थी को क्रमश 10 और 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और इनकी उम्र सीमा 35 से 45 और 32 से 40 क्रमशः रखी गयी है। **(शेष पेज 6 पर)**

साप्ताहिक
समय माया

मिनटों में ऐसे करें नकली और असली हल्दी की पहचान

घर की रसोई से लेकर पूजा-पाठ में इस्तेमाल किए जाने तक के लिए हल्दी का खास महत्व है। यहां तक कि कई बीमारियों से दूर रखने के अलावा हल्दी का इस्तेमाल कई रोग में मददगार भी होता है। इसके गुणों को गिनाने बैठे तो सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन ये जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। हालांकि, ये आपकी एक छोटी सी गलती के कारण हो सकता है।

सरल भाषा में कहें तो हल्दी खरीदने के दौरान की गई लापरवाही या असली हल्दी की सही पहचान न होने पर आपके लिए हल्दी का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। आज हम आपको असली और नकली हल्दी के बीच अंतर करने का आसान तरीका बताएंगे। असली हल्दी की पहचान करने की ट्रिक बहुत ही आसान है और आप मिनटों में पता कर लें कि आप नकली हल्दी लेकर आए हैं या फिर असली?

ऐसे करें नकली और असली की पहचान

सबसे पहले दो अलग-अलग कांच के गिलास लीजिए। इसके बाद दोनों कांच के गिलास में पानी भर लीजिए। अब एक-एक चम्मच हल्दी दोनों ग्लास में डाल लीजिए। शुद्ध हल्दी गिलास में नीचे बैठ जाएगी, लेकिन मिलावटी हल्दी घुल जाएगी।

इसके अलावा हल्दी में अगर कोई रंग मिला होगा तो हल्दी पीली की जगह लाल रंग में भी हो सकती है। आपको बता दें कि मिलावटी हल्दी के कई नुकसान हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पता चल जाए कि जिस हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी है या कहें कि नकली है तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें।

हल्दी खाने के नुकसान

सेहत के लिए हल्दी का अधिक इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि नकली हल्दी या अधिक हल्दी खाने से सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है।

आयरन की कमी

किडनी स्टोन का खतरा

ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना

डाइजेशन संबंधित परेशानियां

डायरिया की समस्या

जानकारी के लिए बता दें कि मिलावटी हल्दी टॉक्सिक हो सकती है। पाउडर वाली हल्दी से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह की हल्दी में जौ का आटा या कसावा स्टार्च मिला हो सकता है। ऐसी नकली हल्दी की पहचान करना मुश्किल है। मिलावटी हल्दी ग्लूटेन इन्टॉलरेंस और सीलियक डिजीज के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ●

महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं मोरिंगा

पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा अपने शक्तिशाली गुणों की वजह से कई समस्याओं से राहत दिलाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर पौधा है, जिसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके औषधीय गुणों की वजह से इसे चमत्कारी पेड़ के रूप में भी जाना जाता है और इसलिए इसके पत्तों से लेकर फूल और फली तक का अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है।

आमतौर पर लोग लोग वजन घटाने, त्वचा की देखभाल, बालों की देखभाल अन्य समस्याओं के लिए विभिन्न तरीकों से मोरिंगा का लाभ उठाते हैं। ऐसे में आज आर्टिकल में हम आपको बताएंगे मोरिंग से महिलाओं को होने वाले कुछ फायदे-

वेट मैनेजमेंट में फायदेमंद

मोरिंगा मेटाबॉलिज्म और फैट तोड़ने में मदद करता है और इस तरह यह वजन कम करने में मददगार होता है। ऐसे में जो महिलाएं अपना वजन अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज करना चाहती हैं, वह अपनी डाइट में मोरिंगा जरूर शामिल करें।

पाचन स्वास्थ्य में सुधार

इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही मोरिंगा को डाइट में शामिल करने से कब्ज को रोकने में मदद मिलती है, जो विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं में एक आम समस्या है।

प्रजनन स्वास्थ्य बेहतर बनाए

"हेल्थ विशेषज्ञों की मानें तो मोरिंगा को हार्मोन बैलेंस करने और महिलाओं में प्रजनन क्षमता में सुधार करने के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन कंटेंट इसके इस गुण के लिए जिम्मेदार है।

ब्लड शुगर कंट्रोल करे

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो मोरिंगा को डाइट में शामिल करने से काफी फायदा मिलेगा। इसमें ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

गठिया में गुणकारी

अपने एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों की वजह से मोरिंगा महिलाओं में गठिया और अन्य सूजन संबंधी समस्याओं के लक्षणों को कम करता है।

दिल को बनाए हेल्दी

इन दिनों महिलाओं में भी दिल से जुड़ी समस्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मोरिंगा का अपनी डाइट में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

स्किन को हेल्दी बनाए

मोरिंगा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और एक त्वचा को युवा बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके लिए आप मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल फेस मास्क की तरह से कर सकते हैं। ●

प्रेग्नेंसी में महिलाएं भूलकर भी न पिएं ये जूस

प्रगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाएं कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चा और मां दोनों की सेहत पर पड़ सकता है। उन्हीं चीजों में से एक है गन्ने का रस। वैसे तो गन्ने का रस प्रेगनेंसी के दौरान बेहद उपयोगी होता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसके बारे में महिलाओं को पता होना जरूरी है। आज हम आपको बताते हैं कि यदि महिलाओं के जरूरत से ज्यादा गन्ने का रस पीने से सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं?

गन्ने का रस पीने के नुकसान

जैसा कि हमने पहले भी बताया प्रेगनेंसी के दौरान गन्ने का रस पीना बेहद उपयोगी होता है। इसके अंदर कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा गन्ने का रस प्रेगनेंसी के दौरान समस्याओं का सामना पैदा कर सकता है। बता दें कि गन्ने के अंदर पॉलीकोसानॉल नाम का तत्व मौजूद होता है, जिससे जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो पेट खराब की समस्या, चक्कर आने की समस्या, नींद ना आने की समस्या यानी अनिद्रा का शिकार हो जाना, सिर में दर्द होना, वजन कम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान गन्ने के रस का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। बता दें कि गन्ने के रस में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे न केवल वजन बढ़ सकता है बल्कि गर्भकालीन मधुमेह का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में गर्भावस्था में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को शुगर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ●

तेज गुस्से को इस तरह करें शांत

अक्सर लोगों को देखा होगा कि किस तरह से वे एकदम गुस्से में लाल-लाल आंखें कर लेते हैं छोटी-छोटी बातों पर और गुस्से में कई गलत फैसले ले लेते है, जिसके कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में यदि गुस्से को

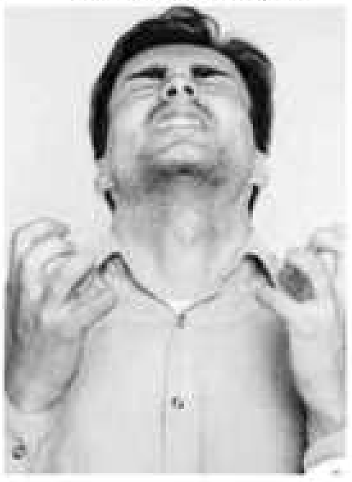

ही तुरंत शांत कर दिया जाए तो आप कई गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। आइये जानते हैं कि किस तरह से गुस्से को शांत कर सकते हैं।

गुस्सा आने पर करें ये काम

यदि आपको बहुत तेज गुस्सा आए या मूड खराब हो जाए तो ऐसे में आप 3 लंबी लंबी गहरी सांस लें। ऐसा करने से आपको तनाव कम होता हुआ महसूस होगा। गुस्से में अपना काबू ना कोई अपने मन को शांत करें और जिस बात से आपको गुस्सा आया है उस बात को अलग तरीके से सोचें और फिर शांति में अलग रिएक्शन के बारे में सोचें।

यदि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या आपका मन अशांत हो रहा है तो ऐसे में आप वॉक करने के लिए चले जाएं। बस 5 मिनट की वॉक न केवल स्ट्रेस को दूर करने में उपयोगी है बल्कि इससे आपका गुस्सा भी कम होता नजर आएगा। यदि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो ऐसे में आप जोर-जोर से गाने गाएं इससे मानसिक और शारीरिक तौर पर आपको अच्छा महसूस होगा। यदि आपको गुस्सा आ रहा है ऐसे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करके खुद को पिंच करें। यदि आपको तेज गुस्सा आ रहा है तो ऐसे में आप सबसे पहले समस्या को पहचानें और देखें कि कौन सी बात आपको ट्रिगर कर रही है। उसके बाद आप परिस्थिति को समझें और दोस्तों में रिश्तेदारों से बात करें। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा। ●

गोगा नवमी पूजन से श्रद्धालुओं को मिलता है मनवांछित फल

गोगा नवमी की त्यौहार वाल्मीकि समाज अपने आराध्य देव गोगा देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाता है। यह गांव तथा शहरों में परम्परागत भक्ति, श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पूजा श्रावणी पूर्णिमा से प्रारम्भ हो जाती है जो नवमी तक चलती है।

जानें गोगा जी के बारे में

गोगाजी को राजस्थान राज्य में लोक देवता के रूप में माना जाता है और लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मण्डलिक व जाहर पीर के नाम जानते हैं। यह गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के छह सिद्धों में गोगाजी का प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है की अगर किसी के घर में सांप निकले तो गोगाजी को कच्चे दूध का छिटा लगा दें इससे सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता हैं । जिस घर में गोगा जी की पूजा होती हैं उस घर के लोगो को सांप नहीं काटता है गोगाजी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं।

गोगा नवमी की कथा

गोगा नवमी से जुड़ी एक कथा है प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जब गोगा की शादी के लिए राजा मालप की बेटी सुरियल को चुना गया तो राजा ने शादी करने से मना कर दिया। इससे गोगा दुखी हुए और उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ को यह बात बतायी। इस पर गोरखनाथ ने वासुकी नाग को राजा की बेटी पर विष से प्रहार करने को कहा। वासुकी नाग के विष के प्रहार को राजा के वैद्य नहीं तोड़ पाए। इस पर वासुकी वेष बदल कर राजा के पास गए और उनसे गुग्गल मंत्र का जाप करने को कहा। गुग्गल मंत्र के जाप से विष का असर कम हो गया। इसके बाद राजा अपने वचन के अनुसार गोगा देवता से अपनी बेटी की शादी कर दी।

गोगा नवमी 2024 की तिथि एवं दिन

हिंदू पंचांग के अनुसार गोगा नवमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाया जाता है। जाहिर है, यह तिथि 27 अगस्त को प्रातः 2:20 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त 2024 को प्रातः 1:33 बजे समाप्त होगी।

पूजन विधि

'गोगा नवमी' के दिन सांपों का पूजन किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि कर भोग का खाना बनाएं जाते हैं। भोग के लिए खीर, चूरमा और गुलगुले बनाए जाते हैं। फिर, महिलाएं वीर गोगा जी की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती है और उन्हें भोग लगाती हैं। कई स्थानों पर गोगा देव की घोड़े पर चढ़ी हुई मूर्ति का पूजन किया जाता है। इस दिन घोड़े को दाल खिलाई जाती है। मान्यता है कि, रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई को जो राखी बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा देव को अर्पित की जाती है। साथ ही उनसे रक्षा की प्रार्थना की जाती है।

राष्ट्रीय खेल दिवस

जानिए मेजर ध्यानचंद की याद में क्यों मनाया जाता है?

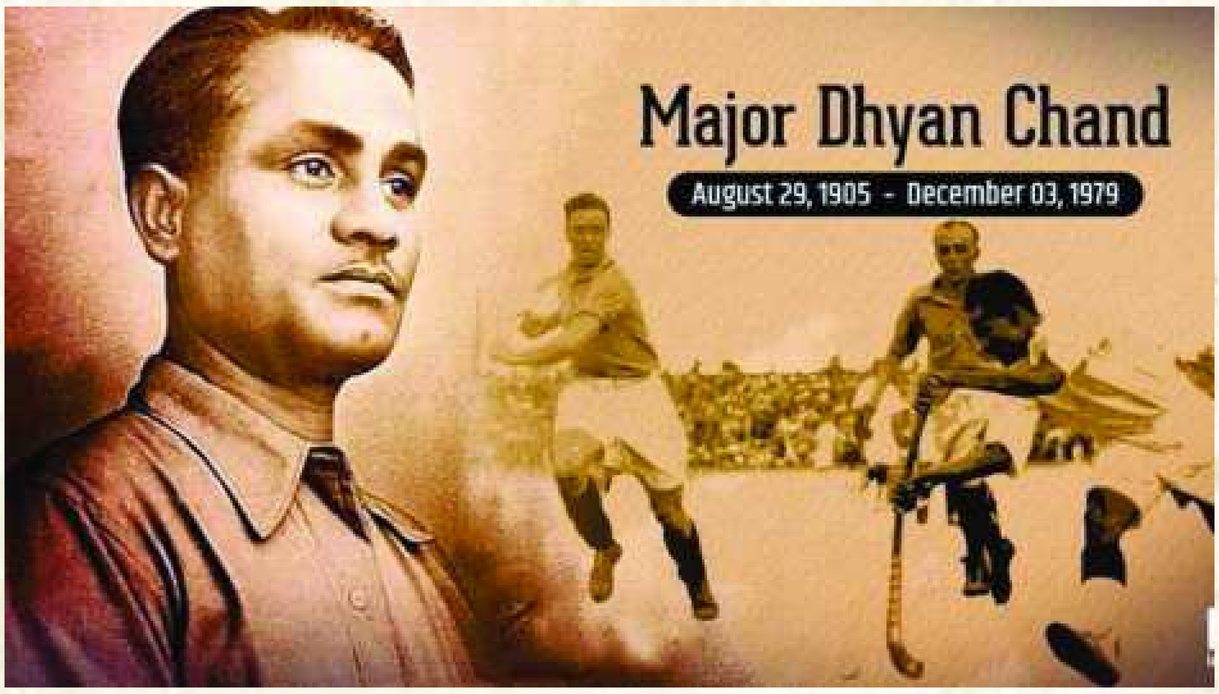

पुराने समय में खेल-कूद को कम महत्व दिया जाता था परंतु तेजी से बदलाव आता गया और खेल का प्रचलन बढ़ने लगा। आज हमारे देश में अच्छा खेल प्रदर्शन करने वाले काफी अच्छे खिलाड़ी राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश में खेलों का बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया है। यह राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में।

राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है?

प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त का दिन हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यान चंद्र के जन्मदिवस पर उनके सम्मान में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2012 से मनाया जाता आ रहा है। इस दिन स्कूलों कॉलेजों आदि में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास

राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान् खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 मे हुई।दुनिया भर में 'हॉकी के जादूगर' के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान् व कालजयी हॉकी खिलाड़ी 'मेजर ध्यानचंद सिंह' जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मेजर ध्यानचंद का जन्म

ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में उत्तरप्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ। इस दिग्गज ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने तीनों ही बार गोल्ड मेडल जीता ।

मेजर ध्यानचंद के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं

महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती होने वाले ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह भी अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में कई गोल दागे थे। आइए नीचे विस्तार से जानते हैं हॉकी के इस महान खिलाड़ी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में-

- सेना में काम करने के कारण उन्हें अभ्यास का मौका कम मिलता था।
- इस कारण वे चांद की रौशनी में प्रैक्टिस करने लगे।
- ध्यान सिंह को चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करता देख दोस्तों ने उनके नाम साथ 'चांद' जोड़ दिया, जो बाद में 'चंद' हो गया।
- ध्यानचंद एम्सटर्डम में 1928 में हुए ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे।
- यहां उन्होंने कुल 14 गोल कर टीम को गोल्ड मेडल दिलवाया था।
- उनका खेल देख एक स्थानीय पत्रकार ने कहा था, जिस तरह से ध्यानचंद खेलते हैं वो जादू है, वे हॉकी के 'जादूगर हैं।
- ध्यानचंद का खेल पर इतना नियंत्रण था कि गेंद उनकी स्टिक से लगभग चिपकी रहती थी।
- उनकी इस प्रतिभा पर नीदरलैंड्स को शक हुआ और ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर इस बात की तसल्ली की गई, कहीं वह चुंबक लगाकर तो नहीं खेलते हैं।
- मेजर की टीम ने साल 1935 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था।
- यहां उन्होंने 48 मैच खेले और 201 गोल किए। क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन भी उनके कायल हो गए।
- उन्होंने कहा, वो (ध्यानचंद) हॉकी में ऐसे गोल करते हैं, जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं।
- वियना में ध्यानचंद की चार हाथ में चार हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई और दिखाया कि वे कितने जबर्दस्त खिलाड़ी थे।

मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियां

मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व मे हॉकी के क्षेत्र में वर्ष 1928, 1932 और 1936 में तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंद को उनके शानदार स्टिक-वर्क और बॉल कंट्रोल की वजह से हॉकी का 'जादूगर' भी कहा जाता था। उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से अधिक गोल किए। भारत सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया।

आत्मकथा

ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम 'गोल' है। आत्मकथा 'गोल' के अनुसार मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी करियर में लगभग 570 गोल किए थे।

देहांत

ध्यान चंद लीवर के कैंसर से ग्रस्त थे। अन्तिम समय में वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। आखिरकार मेजर ध्यान चंद नामक यह सूर्य 3 दिसम्बर 1979 (74 years 3 months 5 days) को हमेशा के लिए अस्त हो गया।

ठुकरा दिया था हिटलर का प्रस्ताव

भारत की आजादी से पूर्व हुए ओलंपिक खेल में सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीम जर्मनी को 8-1 से हराने के बाद जर्मन तानाशाह हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपनी सेना में उच्च पद पर आसीन होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकराकर भारत और भारतीयों का सीना सदा-सदा के लिए चौड़ा कर दिया था।

राष्ट्रपति भवन में होता है उत्सव

हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस समारोह राष्ट्रपति भवन में होता है जहां पर भारत के राष्ट्रपति खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के कारण सम्मानित करते हैं। वह खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कारों से पुरस्कृत करते हैं।

साप्ताहिक समय माया

WHO के इशारे पर नाचना बंद करें विश्व के देशों की सरकारें...

पेज 1 का शेष

समिति ने डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र में एमपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के प्रयासों का समर्थन करने में समन्वित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी- जिसमें टीकों, चिकित्सा और निदान तक पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना; रोग के उछाल का अनुभव करने वाले राज्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना; और डब्ल्यूएचओ और अफ्रीका सीडीसी सहित भागीदारों द्वारा सहक्रियात्मक पहल शामिल हैं।

फिर भी, समिति ने संकेत दिया कि एमपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने में राज्यों के अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोणों का विकास आवश्यक है। इस संबंध में, समिति का मानना है कि महानिदेशक द्वारा यह निर्धारित करना कि एमपॉक्स में वृद्धि एक पीएचईआईसी का गठन करती है, प्रकोपों का सामना करने वाले राज्य पक्षों को घरेलू संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबद्ध करने और नियोजित करने के लिए प्रेरित करेगी। एमपॉक्स में वृद्धि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक द्वारा राज्य पक्षों को जारी की गई अस्थायी सिफारिशें ये अस्थायी सिफारिशें एमपॉक्स में वृद्धि का अनुभव करने वाले राज्य पक्षों को जारी की जाती हैं, जिनमें कांगो और बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा के लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इनका उद्देश्य एमपॉक्स के लिए मौजूदा स्थायी सिफारिशों के अलावा उन राज्य पक्षों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, जिन्हें 20 अगस्त 2025 तक बढ़ाया जाएगा और आसान संदर्भ के लिए इस दस्तावेज़ के अंत में प्रस्तुत किया गया है। एमपॉक्स रोग के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के रणनीतिक ढांचे में उल्लिखित वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में - 2024-2027, उपर्युक्त स्थायी सिफारिशें सभी राज्य दलों पर लागू होती हैं। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के इस पृष्ठ पर सभी मौजूदा डब्ल्यूएचओ अंतरिम तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शन को विकसित स्थिति, अद्यतन वैज्ञानिक साक्ष्य और डब्ल्यूएचओ जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप अद्यतन किया गया है और इसे जारी रखा जाएगा ताकि एमपॉक्स की रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए डब्ल्यूएचओ रणनीतिक ढांचे के कार्यान्वयन में राज्य दलों का समर्थन किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) (IHR) के अनुच्छेद 3 सिद्धांत के अनुसार, इन अस्थायी सिफारिशों के साथ-साथ एमपॉक्स के लिए स्थायी सिफारिशों का कार्यान्वयन, राज्यों द्वारा व्यक्तियों की गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए पूर्ण सम्मान के साथ किया जाएगा, जो IHR के अनुच्छेद 3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप होगा। आपातकालीन समन्वय राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय व्यवस्था स्थापित करना या बढ़ाना;

-जवाबदेही तंत्र शुरू करने सहित सहयोग के माध्यम से प्रतिक्रिया गतिविधियों में लगे या उनका समर्थन करने वाले सभी भागीदारों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना या बढ़ाना;

-असुरक्षा वाले क्षेत्रों या आंतरिक या शरणार्थी आबादी के विस्थापन वाले क्षेत्रों और असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के संदर्भ में मानवीय कार्यकर्ताओं सहित सहयोग और समर्थन के लिए भागीदार संगठनों को शामिल करना;

सहयोगी निगरानी और प्रयोगशाला निदान

-अपनाए गए तरीकों की संवेदनशीलता को बढ़ाकर और व्यापक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करके निगरानी को बढ़ाना;

-नमूनों के परिवहन की व्यवस्था को मजबूत करने, निदान के विकेंद्रीकरण और जीनोमिक अनुक्रमण करने की व्यवस्था के माध्यम से मंकीपॉक्स वायरस क्लेड्स

को अलग करने के लिए सटीक, सस्ती और उपलब्ध निदान तक पहुंच का विस्तार करना;

-आगे के संचरण को रोकने के लिए एमपॉक्स वाले लोगों के संपर्कों की पहचान, निगरानी और समर्थन करना;

-संचरण के तरीकों को स्पष्ट करने और घरेलू सदस्यों और समुदायों में इसके आगे के संचरण को रोकने के लिए एमपॉक्स रोग के मामलों और प्रकोपों की गहन जांच करने के प्रयासों को बढ़ाना;

-एमपॉक्स के संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट समय पर और साप्ताहिक आधार पर डब्ल्यूएचओ को दें;

सुरक्षित और स्केलेबल क्लिनिकल देखभाल

-एमपॉक्स के रोगियों के लिए क्लिनिकल, पोषण और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें, जिसमें आवश्यकतानुसार और संभव हो तो देखभाल केंद्रों में अलगाव और घर-आधारित देखभाल के लिए मार्गदर्शन शामिल है;

एमपीओएक्स से पीड़ित सभी रोगियों, जिनमें बच्चे, एचआईवी से पीड़ित रोगी और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, के लिए अनुकूलित सहायक नैदानिक देखभाल तक पहुंच का विस्तार करने के लिए एक योजना विकसित और कार्यान्वित करना। इसमें वयस्क रोगियों को एचआईवी परीक्षण की पेशकश करना शामिल है, जो अपनी एचआईवी स्थिति नहीं जानते हैं और बच्चों को उचित रूप से एचआईवी उपचार और देखभाल सेवाओं से लिंक करना, जब संकेत दिया जाता है; मलेरिया, वैरिकाला ज़ोस्टर और खसरा वायरस जैसे स्थानिक सह-संक्रमणों की शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन, और यौन संपर्क से जुड़े मामलों में अन्य यौन संचारित संक्रमण एसटीआई;

-नैदानिक और संक्रमण और रोकथाम और नियंत्रण मार्गों में स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ताओं की क्षमता, ज्ञान और कौशल को मजबूत करना - संदिग्ध और पुष्टि किए गए एमपीओएक्स वाले रोगियों के निदान से लेकर छुट्टी तक - और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना;

-स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, घरेलू सेटिंग्स, सामूहिक सेटिंग्स (जैसे जेल, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति और शरणार्थी शिविर, स्कूल, आदि) और सीमा पार पारगमन क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों और बुनियादी जल और स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देना और लागू करना;

अंतर्राष्ट्रीय यातायात

-एमपॉक्स के संदिग्ध मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए सीमा पार सहयोग व्यवस्था स्थापित करना या उसे मजबूत करना, यात्रियों और परिवहन संचालकों को जानकारी प्रदान करना, स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अनावश्यक रूप से प्रभावित करने वाले सामान्य यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों का सहारा लिए बिना;

टीकाकरण

-राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूहों को बुलाने, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों को जानकारी देने, उपलब्ध तंत्रों के माध्यम से टीकों के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय नीति तंत्र तैयार करने के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एमपॉक्स वैक्सीन की शुरूआत की तैयारी करना;

-संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे, यौन संपर्क, बच्चों और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं सहित मामलों के संपर्क को लक्षित करते हुए, घटना के मामलों यानी पिछले 2-4 सप्ताह में बीमारी की शुरुआत के साथ वाले क्षेत्रों में प्रकोप प्रतिक्रिया के संदर्भ में एमपॉक्स टीकाकरण गतिविधियों को आगे बढ़ाने की योजनाएँ शुरू करना। इसमें संबंधित क्षेत्रों में टीकाकरण रणनीतियों और योजनाओं का त्वरित अनुकूलन शामिल है; टीकों और आपूर्ति की उपलब्धता; टीकाकरण की मांग और उस पर भरोसा पैदा करने और उसे बनाए रखने के लिए सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव; और कार्यान्वयन योग्य अनुसंधान प्रोटोकॉल के अनुसार टीकाकरण के दौरान डेटा का संग्रह;

जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव

- प्रकोप की रोकथाम, प्रतिक्रिया और टीकाकरण रणनीतियों के लिए प्रभावित समुदायों और स्थानीय कार्यबलों के साथ जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव प्रणालियों को मजबूत करना, जिसमें प्रशिक्षण, उच्च जोखिम और कमजोर आबादी का मानचित्रण, सामाजिक सुनवाई और सामुदायिक प्रतिक्रिया, गलत सूचना का प्रबंधन शामिल है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एमपॉक्स के प्राकृतिक इतिहास के बारे में अनिश्चितताओं, एमपॉक्स के बारे में अद्यतन जानकारी, जिसमें चल रहे नैदानिक परीक्षणों से जानकारी, एमपॉक्स के खिलाफ टीकों की प्रभावकारिता और टीकाकरण के बाद सुरक्षा की अवधि के बारे में अनिश्चितताओं के बारे में प्रभावी ढंग से संवाद करना शामिल है;

-सार्थक सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से किसी भी तरह के कलंक और भेदभाव को संबोधित करना, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में और जोखिम संचार गतिविधियों के दौरान; शासन और वित्तपोषण

-रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया गतिविधियों के लक्षित वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय वित्त पोषण को बढ़ावा देना और बढ़ाना और बाहरी अवसरों का पता लगाना;

-मौजूदा कार्यक्रमों में एमपॉक्स की रोकथाम और प्रतिक्रिया उपायों को एकीकृत करना, जिसका उद्देश्य अन्य स्थानिक रोगों - विशेष रूप से एचआईवी, साथ ही एसटीआई, मलेरिया, तपेदिक और कोविड-19, साथ ही गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार करना है - और जहाँ तक संभव हो, उनके वितरण पर नकारात्मक प्रभाव न डालने का प्रयास करना;

https://www.who.int/news/item/19-08-2024-first-meeting-of-the-international-health-regulations-2005-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024

सत्ता में सीधे प्रवेश करवा, हित चिंतन व सत्ता सुख भोग

पेज 3 का शेष

विज्ञापन आने के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ढेर सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम एण, एऊ और ध्ँ वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है।

राहुल गांधी का कहना था कि 'चंद कॉरपोरेट्स' के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का INDIA मजबूती से विरोध करेगा। 'IAS का निजीकरण' आरक्षण खत्म करने की 'मोदी की गारंटी' है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव तक ने इसका विरोध किया है। खड़गे ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी जान बूझ कर नौकरियों में इस तरह की भर्ती कर रही है जिससे एससी, एसटी और ओबीसी हिस्से को आरक्षण से दूर कर दिया जाए।

उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या इनमें एससी, एसटी और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संविधान को दो टुकड़ों में फाड़ दिया है। और इस तरह से आरक्षण पर दोहरा हमला कर दिया है। इसके साथ ही उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार के आरक्षण घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। वह कल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 69000 अध्यापकों की भर्ती मामले में फैसले की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि लैटरल प्रवेश की शुरुआत 2018 से हुई थी जब नीति आयोग और सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने सरकार को अपनी 2017 की रिपोर्ट में इसकी संस्तुति की थी। इसी 8 अगस्त को केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया था कि सीधे प्रवेश के तहत अब तक कुल 63 नियुक्तियां हो चुकी हैं। और ये सभी संयुक्त सचिव, निदेशक और डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर की हैं। मौजूदा समय में 57 अधिकारी जो यथार्थ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों आईटीसी युनिलीवर अडानी अंबानी आदि के प्रतिनिधि और अधिकारियों व नेताओं की मूढ़ औलादें सीधे ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पदस्थ हैं।

आरजेडी मुखिया लालू यादव ने एक्स पर दिए गए अपने बयान में कहा है कि बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत कोई आरक्षण नहीं है। कॉरपोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानि खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह 'नागपुरिया मॉडल' है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर NDA के लोग डाका डाल रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाज़े से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साज़िश कर रही है, उसके खिलाफ़ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है।

ट्विटर पर अपने लंबे बयान में उन्होंने कहा कि ये तरीक़ा आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे।

दरअसल से सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गयी है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ़ देश भर का पीडीए जाग उठा है तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है।

इंजीनियर अधिकारी चुने नेता सब का उद्देश्य भ्रष्टाचार से लूट

पेज 8 का शेष

कचरा कहां फंसा हुआ और कैसे सफाई की जाए? वर्तमान में यह हो रहा है कि किसी भी रहवासी ने किसी भी निगम के आसपास के कार्यालय में पानी न निकलने की शिकायत की तो दो तीन चार बार पैसे लेकर सफाई करने वाले पहुंचते हैं जब नहीं होता है तो नई लाइन डाल दी जाती है। अंबेडकर नगर में 20 साल में करीबन 5 लाइन डाल दी गई यही हाल पूरे इंदौर शहर का है जहां हर वर्ष हजारों करोड रु. विभिन्न योजनाओं के नालियां बनाने बैकलाइन व सड़के खोदने नई लाइन बिछाने में 40 से 80% कमीशन पर खर्च किया जाता है। पर समस्या वही यथावत रहती हैं। रहेगी। इंदौर में बीआरटीएस बनाते समय भी लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अग्रवाल और कार्यपालन यंत्री संभाग 1 इंजी आर के सावला, नर्मदा जलापूर्ति संभाग दो इंदौर नगर निगम संजीव श्रीवास्तव से भी बोला गया के सब गलत हो रहा है। बीआरटीएस की सड़क के दोनों तरफ एक-एक वर्ग मीटर की पक्की घंतियां ताकि उसमें हर प्रकार के जलापूर्ति, गैस अन्य पाइप लाइन बिना खुदाई डाली जा सके और हर 200 मीटर पर क्रॉस सेक्शन बनाने की बात की थी। जबकि वह सब बीआरटीएस बनाते समय उसकी समिति में बैठते, सलाह करते थे। पर जानबूझकर दोनों तरफ पहले नालियां व बाढ निकासी नहीं बिछाई गई। साढे 1100 करोड़ की इस 11.5 सड़क जबकि उस समय लागत रू. 5 से 6 करोड रुपए प्रति किलोमीटर थी। सबका ध्यान करोड़ों रुपए के कमीशन पर लगा हुआ था। आज हालात सामने है। थोड़ी सी ही बरसात में हर चौराहे पर जाम सड़कें नहरे बन जाती हैं। चौराहे 3-4 फुट तक पानी से भरे भारी तालाब बन जाते है। हाल ही में हर चौराहे पर बना रहे जितने भी फ्लाईओवर हैं उनमें भी अगर मोती कमीशनखोरी की गई और सही प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। तो हर बरसात में यह समस्याएं और गहरी होंगी। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री दावा करते थे की सन 2010 से पूरे प्रदेश के सभी विभागों को ऑनलाइन कंप्यूटराइज कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारियां ऑनलाइन की जा रही है। तो 14 वर्ष गुजर जाने के बाद में भी प्रदेश के सभी नगर निगमों पालिकाओं की खरीदी बिक्री कार्यों की सारी विस्तृत परियोजना विवरण या डीपीआर निविदाएं कार्या देश कार्यों की समीक्षायें, संबंधित ठेकेदारव उनके इंजीनियर की टिप्पणियां उनकी नाप पुस्तिकाएं सब ऑनलाइन क्यों नहीं किए जाते? मध्य प्रदेश के ग्रामीण सड़क, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व अन्य में कुछ कार्यों निविदायें, एमबी, टिप्पणियां भुगतान आदि ऑनलाइन कर दिए हैं तो नगर निगम पालिकाएं क्यों नहीं करती ताकि जनता देख सके कि आखिर उससे जबरदस्ती थोपे गये करों से लूटा हुआ धन कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है और उस धन का सदुपयोग हो रहा है। या भविष्य में दुरुपयोग सिद्ध होगा। पिछले 4 दिन में हुई भारी बरसात पर सभी समाचार पत्रों ने आधे अधूरे ज्ञान और पूरे फोटो के साथ टिप्पणियां की हैं। कुछ की फोटो नीचे चिपकाए जा रहे हैं।

चोरल में निर्माणाधीन छत गिरने से 5 लोगों की मौत पर लीपापोती

पेज 8 का शेष

इसके बारे में भोपाल के नगर निगम के मृत व जीवित श्रमिकों के फर्जी भुगतान के बारे में काफी समाचार समाचार पत्रों में छापे गए। जबकि उद्योगों व निर्माणाधीन साइटों पर दुर्घटना होने घटने पर सारी जांच पड़ताल कानूनी कार्यवाही न्यायालयों में प्रकरण लगाने से लेकर लड़ाई यह विभाग करता है। जिम्मेदार भी इसी को ठहराया जाता है। और इसी चक्कर में जो हरदा में पटाखा निर्माण के परिसरों में जो विस्फोट से हजारों श्रमिकों की मौत हुई थी। जिसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता था केवल 5 से ज्यादा बड़े-बड़े परिसरों में बाल श्रमिकों व वयस्क मजदूरों से पटाखे बनवाये जाते थे। उसमें भी बारूद के लाइसेंस कैंपस आदि की परमिशन जिलाधिकारी एडीएम एसडीएम और पटवारी के माध्यम से ली गई थी। श्रमिकों का पंजीयन नियमन हरदा के श्रम अधिकारी व निरीक्षक के अंतर्गत होने के साथ सहायक आयुक्त श्रम विभाग होशंगाबाद या नर्मदा पुरम संभाग के अंतर्गत था। जो लाखों में घातक विस्फोटक बारूद के उपयोग के बारे में सब जानने के बाद में मोटा महीना वसूलते थे। जबकि वहां मशीनों और विद्युत शक्ति से कोई कार्य संपन्न नहीं होने के बाद में भी भोपाल के प्रभारी उपसंचालक और मध्य प्रदेश से इंदौर मुख्यालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभारी संचालक अजय पाल सिंह के साथ सहायक संचालक नवीन बरूआ वर्तमान पदस्थापना बीना कार्यालय को औद्योगिक दुर्घटना के आधार पर 06 व 8 मार्च 2024 को निलंबित कर दिया गया। जबकि नवीन बरुआ का उसे बुक से कोई लेना-देना नहीं था परंतुपूर्व में भी जब नवीन बरुवा भोपाल कार्यालय में पदस्थ थे। जब पूर्व में भी हरदा में हुई दुर्घटना पर संबंधित मलिक के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण लगाया। चूंकि उनके विभाग को कोई भी अलग से वकील नहीं मिलता सरकारी वकील ही इनका प्रकरण की पैरवी करते हैं। संबंधित प्रकट में भी सरकारी वकीलों से लेनदेन के कारण यह प्रकरण हार गए। उस पूर्व प्रकरण के हारने के आधार पर निलंबित कर दिया गया।

और इस हरदा के विस्फोट कांड मामले में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। परंतु हरदा का श्रम निरीक्षक महेंद्र सिंह को एक माह बाद निलंबित किया गया। जानबूझकर श्रम अधिकारी का पद रिक्त रखा गया है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की सहायक आयुक्त घोर भ्रष्ट जालसाज जैसमिन अली सितारा जो पूर्व में संनिर्माण कर्मकार मंडल की सचिव रह करोड़ों के घोटाले कर चुकी है। और पत्रकारों द्वारा जानकारी मांगने पर उनको छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मारपीट करवा अंदर करवा चुकी है। ताकि श्रमिकों के बच्चों के नाम पर किए गए पुस्तकों, कॉपीयों ड्रेस छात्रवृत्ति आदि के नाम पर किए गए घोटाले में बचा जा सके। इसमें से किसी को भी जिम्मेदार होने के बाद में भी निलंबित नहीं किया गया। वही हाल जैसा की 22 मार्च को चोरल में हुई दुर्घटना के मामले में इंदौर के प्रभारी उपसंचालक हर्ष चतुर्वेदी को समाचार पत्रों में जिम्मेदार बताया जा रहा है। जबकि इस कार्य में पंचायत के सचिव सरपंच के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों जिन्होंने नक्शा स्वीकृत किया। जिम्मेदार पटवारी तहसीलदार से पूछताछ कर जांच बैठाई जानी चाहिए।

दूसरी तरफ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग जिसमें राजधानी में प्रमुख अभियंता, संभागीय स्तर पर मुख्य अभियंता होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत के अंतर्गत पूरा संभागीय कार्यालय जिसमें कार्यपालन यंत्री से लेकर उपयंत्रियों की फौज होती है। उसको सभी प्रकार के निजी व सरकारी कॉलोनी नगर नियोजन निर्माण आदि की लोक निर्माण विभाग की तरह देखरेख नियमन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिये। वर्तमान में इतना बड़ी पूरे प्रदेश भर में विभागीय संरचना के अधिकांश 55 जिलों के कार्यपालन और सहायक यंत्रियों के पास खास कोई काम नहीं है। मनरेगा का काम जिला पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों के पास 40 लाख तक के काम सौंप रखे हैं। जिन सरपंचों को अंगूठा लगाना और मुंह धोना नहीं आता। बिना डीपीआर और देखरेख के रुपए 40 लाख तक के कार्यो की स्वीकृति के सामुदायिक भवन गौशालाओं, पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर अधिकांश कार्य शिवराज सिंह चौहान ने पुनः सत्ता में वापसी लोकसभा विधानसभा चुनावों में ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ाने लूटपाट करवाने के लिए सौंप दिए थे। जैसे जनता से लूटा हुआ धन इन हरामखोरों के बाप की जागीर हो। जब डिग्री डिप्लोमा धारी इंजीनियर बैठे हुए हैं तो उनसे रु.5 लाख से ऊपर के काम ना करवा कर जनता का धन बर्बाद करने लूटने और लुटाने सरपंचों सचिवों से 40 लाख रु तक के काम करवाने का औचित्य क्या है? आखिर रु. 5 लाख से ज्यादा के सभी काम चाहे वह मनरेगा मुख्यमंत्री सड़क योजना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास, गांवों की सड़कें, नालियां, भवन, गौशालायें, सामुदायिक, महिला बाल विकास की आंगनबाड़ियों के भवन, विद्यालय, तालाब, लघु बांध नहरें आदि के निर्माण मरम्मत सुधार कार्य वा अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यों को सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि अधिकतम 1 करोड़ 2 करोड रुपए से ज्यादा कि नहीं होते। क्योंकि ज्यादा बड़े काम लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन विभाग करते हैं। ताकि शासकीय धन का जो वेतन पर खर्च किया जा रहा है। सदुपयोग किया जा सके। चूंकि शासकीय इंजीनियर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्तर पर बनने वाले रिजॉर्ट, फार्म हाउस, फैक्ट्री, कालोनियों आदि के स्तरीय निर्माण मरम्मत के कार्यों की देखरेख भू उपयोग कॉलोनी नगर आदि के नक्शे भविष्य में जल निकासी स्वच्छ वायु हरित क्षेत्र आदि के नियोजन की जानकारियों व नक्शे आदि को ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग के जिलों के संभागीय कार्यालय को प्रेषित किया जाना व स्वीकृति आवश्यक किया जाना चाहिए। ताकि चोरल जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

सारे विभाग खाली, न भर्तीयां न पदोन्नोतियां, न मजदूरी में वृद्धि

पेज 1 का शेष

जबकि काम योजनायें जनसंख्या वृद्धि कंप्यूटराइजेशन व अनेकों नये कार्यों योजनाओं के कारण समय के साथ उसमें कार्यों का बोझ 10 गुना बढ़ गया परंतु नियमित और स्थाई कर्मचारियों की भर्तीयां नहीं की जा रहीं। और लगभग आज अकेले मध्य प्रदेश में सभी विभागों के तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक 70% की कमी होने के कारण जो भर्तीयां की जानी चाहिए। वे हर वर्ग की भर्तीयां नहीं की जा रही। वर्तमान में जो स्टाफ काम कर रहा है। उसमें अनेकों पदों पर लाखों अधिकारी इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक कर्मचारी एक ही पद पर सेवानिवृत हो गये।

पर उन्हें स्थाई पदोन्नतियां व स्थायित्व नहीं दिये गये। बदले में हर 20 साल में लगने वाले टाइम और पे स्केल का भी लाभ व पदोन्नतियां देने की अपेक्षा, अपने ही प्रदेश के विभागों के कर्मचारियों-अधिकारियों को ज्यादा वेतन व सुविधा ना देनी पड़े परंतु उनसे उच्च पद का काम लिया जा सके, नये छल कपट के साथ षड्यंत्र उच्च पद का पदनाम देने का किया गया। सत्ता में चुनकर जिन नेताओं को जनता ने भेजा उन नेताओं ने पूरी तरह अपनी लूट व डकैती के लिए अपने ही कर्मचारियों अधिकारियों के साथ जनता से भी हर तरह का छल कपट किया।

सरकारी विभागों में छोटे पदों पर काम करवाने के लिए नए षड्यंत्रों के साथ ठेके पर बाहरी ठेकेदार से कर्मचारियों सिर्फ छोटे परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करवाये जा रहे हैं। जिसमें अधिकांश विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर जो सारे विभाग का काम करता है। जिन्हें एक ही पदपर 5 से 30 साल हो गए परंतु एक तरफ निर्मित नहीं किया गया तो दूसरी तरफ उनका वही अस्थाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह 5 से 8- 10000 का वेतन दिया जा रहा है। जिसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की विद्युत वितरण कंपनियों में तो हालत अत्यधिक गंभीर है जहां लाइन स्टाफ इसे बिना प्रशिक्षण बिना सुरक्षा उपकरण जिसमें ग्लोब्स मास्क गमबूट वर्दी बरसाती आदि और लाइनों पर काम करने के लिए पाने पिंचीस या प्लायर दिए बिना खाबो पर चढ़ा दिया जाता है और वह अपने मन से ही लाइन पर काम करता है और उसमें हर दिन पिछले 10 सालों से औसतन एक मौत हो रही है जिनको विद्युत वितरण कंपनियों में बैठे हरामखोर जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी जॉइन कंपनियों में मोती कमीशनखोरी खरीदी विद्युत आपूर्ति निर्माण यहां तक की कर्मचारियों के वेतन में हजम करने के लिए आते हैं मृत्यु हो जाने पर या अधिक घायल हो जाने पर इलाज व क्षतिपूर्ति की धंधा की व्यवस्था नहीं करते। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में लगभग 100 से ज्यादा विभाग काम कर रहे हैं परंतु विभागों में राज्य सरकार के प्रथम द्वितीय श्रेणी अधिकारियों तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भर्तीयों की दूर पदोन्नतियां भले ही तो पिछले 10 से 30 सालों से नहीं दी जा रही हों। परंतु भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के चुने हुए भारतीय प्रताड़ना सेवा, भारतीय अपराध संरक्षण सेवा, भारतीय वन लूटो सेवा आदि के अधिकारियों को पिछले 30 सालों से हर 3 साल में न केवल पदोन्नतियां दी जाती हैं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग उनकी नियमित भारतीय करके हर वर्ष मध्य प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारी भेजता है। और हालात यह हैं, कि पूरे प्रदेश में तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर राज्य सेवा के प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी अधिकारियों इंजीनियर डॉक्टरों से लेकर द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के शिक्षकों निरीक्षकों बाबू कंप्यूटर ऑपरेटर तक की भारी कमी होने के कारण सरकार को तत्काल भर्ती की जानी चाहिए।

पूरे प्रदेश भर में हर प्रकार के शासकीय शुल्क इसमें परिवहन में भी केंद्र सरकार की तुलना में अधिकांश शुल्क 10 गुना ज्यादा बासुरी जा रहे हैं। शराब पर भी सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में ही लगता है वही हाल पेट्रोल-डीजल, गैस यहां पर भी देशभर में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा बिकता है यहां पर भी करीब 36% पेट्रोल डीजल गैस पर वेट ठोका जाता है। शिक्षण पंजीयन जो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। लगातार जीएसटी भी जो 1500 से ज्यादा वस्तुओं को ठोका जाता है उसका भी भरपूर पैसा आ रहा है। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी दैनिक वेतन भोगियों संविदा के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें मात्र 8 से रु. 10000 दिए जा रहे हैं। जबकि बिजली में भी जनता को इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट मीटर से 10 गुना ज्यादा तक के बिलों से लूटा जा रहा है

क्योंकि उनको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पर बेशक निर्माण कार्य खरीदी आदि में 10 गुना तक ज्यादा भुगतान कर मोटा कमीशन हजम किया जा रहा है। कृषि उद्यान की वह अनुच्छेद में दी जाने वाली अनुदान राशि को अत्यधिक कम कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है इतना पैसा होने के बावजूद भी मोहन यादव जो पूर्व से ही भू कॉलोनी शराब खनन शिक्षा आदि का कुख्यात माफिया है। अपनी कुकर में भ्रष्टाचार को छुपाने हर दिन की 2,3 पेज के विज्ञापन समाचार पत्रों पत्रिकाओं व्हाट टीवी न्यूज़ चैनल में विभिन्न विभागों के विज्ञापनों के लिये खर्चे में कहीं कोई कमी नहीं आती।

पर अपनी ही सरकार को चलाने के लिए राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के लिए बहाने किये जाते हैं। द्वितीय चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी देने के नाम पर बार-बार कमेटी बनाई जाती है। निर्णय आने पर उसमें कोई ना कोई आनंद का पच्चड़ फंसा कर मजदूरी भुगतान को रोक दिया जाता है। अखंड डकैत हरामखोरों सब अपने आप की जागीर है जो मोती खरीदी मोटे निर्माण के नाम पर 50 से 80% कमिशन पर करवाओ और उसमें पैसा हजम कर जाओ। और अपने ही सरकार के कर्मचारियों को उनके हक का पैसा देने में तरीके से रुलाओ।

खर्चो पर नियंत्रण करने की अपेक्षा सरकार चलाने के लिए बार-बार केंद्र व रिजर्व बैंक के साथ बाजार से भी विभिन्न माध्यमों से हजारों करोड़ का कर्ज लेकर लेकर घी पी रहा है। उसे कर्ज की भरपाई जनता को करनी है। विपक्षी दल कांग्रेस को इन सब बातों को लेकर सड़कों पर उतरकर जनता के साथ आंदोलन करना चाहिए और मांग की जानी चाहिए की सूचना के अधिकार की धारा 4 के अंतर्गत सभी विभागों के सभी खरीदी बिक्री खर्च भुगतान आदि को सार्वजनिक कर जनता के सामने रखें और अपने ही सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को पर्याप्त महंगाई भत्ता वेतन और केंद्र के समान बड़ी हुई मजदूरी तत्काल देने की व्यवस्था करवाई जाए पेट्रोल डीजल गैस पंजीयन परिवहन बिजली-पानी निगम करों मुझे लूट की जा रही है उसकी तत्काल रोका जाए।

हजारों करोड़ खर्च फिर भी बनता वर्षा में सड़कें नहरें, शहर तालाब

इंजीनियर अधिकारी चुने नेता सब का उद्देश्य भ्रष्टाचार से लूट

लावारिस डकैतों के शहर में सड़कों पर 3-4 नालियां बिछाई, केवल लूट की प्लानिंग

इंदौर के साथ पूरे प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों में भू और कॉलोनी माफियाओं के इशारों पर नाचने वाले जिलों के कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक से लेकर जितने भी नगर निगमों पालिकाओं में मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण कार्यपालन सहायक और उप यंत्रियों तक, साथ ही घोर भ्रष्ट नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तक में किसी को भी नगर नियोजन में प्राकृतिक नदियों नालों जल बहाव क्षेत्रों व कान्टूर और टोपो मैप के हिसाब से बसाहट के लिये रहवासी व सड़कें बरसात के पानी की निकासी की ठीक व्यवस्था करने का ना तो कोई ढंग का अनुभव, न ज्ञान और जिम्मेदारी है।

प्रदेश और देश का शहरीय विकास मंत्रालय को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन विभाग साथ मिलकर सबसे पहले शहरीय विकास के मामले में सबसे पहले टोपो और कान्टूर मेप के हिसाब से नये नक्शों पर प्लानिंग कर जल आपूर्ति व निकासी की मजबूत व्यवस्था बनाने के बाद ही कॉलोनाइजरों बसाहटों की व्यवस्था करनी चाहिए। पर प्रादेशिक शहरीय विकास मंत्रालय के मुख्यालयों से चलकर संभागीय व जिला स्तर पर सबके कार्यालय होने के बाद में भी किसी का भी इन पर कोई खास नियंत्रण देखरेख व जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आखिर जनधन से वेतन लेने वाले यह सब संबंधित बैठकर सही तरीके से कान्टूर और टोपो मैप के हिसाब से सामान्य दिनों के हिसाब से बसाहटों की जल निकासी की नालियां बिछाना, वर्षा के बाढ़ के जल की निकासी की व्यवस्था के लिए मोटी 1 मी 1.5, या 2 मी पाइप लाइन, सड़कें बनाने से पूर्व ही डाली जानी चाहिए। बेशक आजादी के पूर्व प्रदेश के अधिकांश महानगरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन आदि में जहां राजाओं ने नगर नियोजन से पूर्व इन सब की ठोस व्यवस्था की थी और यही कारण है कि ग्वालियर में 1910 की बनाई हुई

जल निकासी की व्यवस्था 1980 -90 तक ढंग से चलती रही। वही हाल इंदौर में भी महाराजा तुकोजीराव ने खुली व बंद नालियों की जो व्यवस्था की थी।

परंतु 1990-2000 के बाद भू और कॉलोनी माफिया की बढ़ती लूट और डकैती के कारण जितने भी इंजीनियर अधिकारियों के साथ चुने हुए नेताओं, पार्षदों महापौरों जो स्वयं भू कॉलोनी माफिया थे या उनके संरक्षक थे ने नगर निगमों पालिकाओं को भारी भ्रष्टाचार के लिए नियम कानूनों को ताक पर रख लूट और डकैती का वैधानिक अड्डा बना लिया किसी को कोई मतलब नहीं था और इंदौर में 1998 के बाद जब से वर्तमान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौर का पद संभाला। भारी मोटे भ्रष्टाचार के लिए मोटे ठेके देने के साथ बिना सड़कों की खुदाई किए दोनों तरफ नालियां व बीच में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए मोटी पाइप लाइन बिछाए सड़कों पर आजू-बाजू तोड़फोड़ कर सड़कों पर परत दर गिट्टी सीमेंट डालकर रहवासी क्षेत्रों के तल से 2-3 इंच ऊंची सड़कें बना दी। जिसके कारण उचित जल निकासी न होने के कारण वर्षा होने पर एक तरफ सड़कों पर पानी भरने लगा तो दूसरी तरफ में पानी इकट्ठा होने के बाद रहवासी क्षेत्रों के मकानों के तल जो पूर्व से एक दो फीट ऊंचे थे। डेढ़ दो ढाई तीन फीट सड़कें ऊंची होने के कारण सड़कों के तल से नीचे हो जाने से वर्षा का सड़कों का पानी उनके घरों में भरने लगा और परेशानियां बढ़ने लगीं। सड़के नहरें व तालाब बनने की समस्या हर वर्ष 2, 3, 4 इंच पानी गिरने पर होती है। इस प्रकार बार-बार नालियां खोदने बिछाने सड़के फोड़ने बनाने में पिछले 24 सालों में लगभग 20000 करोड रुपए केंद्र व राज्य के शहरी विकास मंत्रालय से, गंगाजल सफाई अभियान, स्वच्छता मिशन, जल निकासी प्रबंधन निर्माण व उन योजनाओं के अंतर्गत नाली निर्माण के लिए मिलने के बाद भी विश्व बैंक एशियाई बैंक नाबार्ड एचडीएफसी व अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर हजम कर लिया गया। यदि 25 साल के निर्माण कार्यों के बारे मेंनगर निगम और पालिकाओं से उनके नक्शों की जानकारियां ली जाएं। तो निगम और पालिकाओं से लेकर शहरी विकास मंत्रालय और नगर एवं ग्राम निवेश के क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों में भी किसी के पास किसी भी नाली निर्माण खर्च के साथ साफ सफाई करने रख रखाव के लिए दशा और दिशा जानने के लिए नक्शे ही नहीं मिलेंगे। और इन हरामखोर जालसाजों कोई स्मार्टफोन समस्या से कोई मतलब नहीं वे तो जिस क्षेत्र का पार्षद है। उसके आंचलिक कार्यालय में बैठे अधिकारी इंजीनियरों के पास जब बेक लाइन में बनी सीवर लाइन से रह वासियों के शौचालय और स्नानागार का पानी भरने की और पानी घरों में घुसने की समस्या लेकर आता है। तो वह नक्शे निकालकर यह समझना ही नहीं चाहते की पानी क्यों भर रहा है उसका बहाव किस दिशा में आगे वह किस बड़ी नाली से जुड़ता है। (शेष पेज 7 पर)

ग्रामीण क्षेत्र में निजी निर्माण पर ग्रामीण यांत्रिकी के यंत्री हों जिम्मेदार

चोरल में निर्माणाधीन छत गिरने से 5 लोगों की मौत पर लीपापोती

ग्रामीण विकास विभाग में ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा में सैंकड़ों उपयंत्रियों से प्रमुख अभियंता तक के पास कोई खास काम नहीं। 10 लाख रु से ज्यादा के कार्यों की डीपीआर से पूर्णता तक कार्य करवाये जाने चाहिए।

इंदौर के चोरल गांव में चोरल नदी के दोनों किनारों पर इंदौरी धनाढ्यों द्वारा बनवाए जा रहे फार्म हाउस में कमजोर काम चलाऊ सरियै से छत भराई के बाद भारी बारिश का पानी भरने से छत गिरने के कारण उसके नीचे सो रहे पांच मजदूरों की अकाल मौत हो गई। इसमें छत निर्माण का ठेकेदार भी मौत का शिकार हो गया। हल्ला मचा समाचार पत्रों में खबरें छापने पर जिम्मेदारों को ढूंढा गया तो ले देकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं संगठन जहां 40 इंजीनियरों के स्टाफ में से मात्र 7 काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से भर्ती व पदोन्नतियां न करने के कारण पूरा मध्य प्रदेश औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा संगठन का ढांचा पहले से ही बहुत कमजोर है। और 1990 में स्वीकृत तकनीकी व गैर तकनीकी स्टाफ की तुलना में मुख्यालय में ही 15-18% स्टाफ ही बचा है। जबकि पूर्व में केवल उद्योगों के परिसर में मशीनों श्रमिकों कर्मचारी आदि की सुरक्षा व नियमन का जिम्मा था। जबकि वर्तमान में 35 सालों में प्रदेश में उद्योगों व फैक्ट्रियों की संख्या 10 गुना हो चुकी है। उस हिसाब से स्टाफ कम से कम 10 गुणा होना चाहिए था। हर जिले में उसका कार्यालय होना चाहिए। परंतु उसके अधिकांश संभागीय कार्यालयों में भी 10-20% स्टाफ ही बचा है।

सन 2010 के बाद इसमें फैक्ट्री मिल उद्योगों की आंतरिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के साथ निर्माण, सुधार, नवीनीकरण के सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में सड़कें, भवनों, पुल, उद्योग, बांध नहरें आदि के सिविल वर्क को भी शामिल कर वहां सुरक्षित तरीके से निर्माण मरम्मत आदि के कार्य व उनमें लगी मशीनों मजदूरों साइट आदि के स्वास्थ्य सुरक्षा का कार्य भी सौंप दिया गया है। जबकि इन में थोपा गया 2% संनिर्माण कर्मकार कल्याण का कुल शुल्क जो हर सरकारी सिविल वर्क के निर्माण के बिल पर भुगतान किया जाता है। वह श्रम विभाग में बैठे डकैतों के पास जाता है। जो वर्तमान में लगभग 4000 करोड रु से ज्यादा है और उसके अध्यक्ष के रूप में भोपाल में श्रम विभाग का सहायक आयुक्त बैठता है। जो मंत्री संत्री और विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर विभिन्न योजनाओं के 40 से 80% कमीशन पर श्रमिकों के बच्चों के कल्याण हेतु विद्यालय छात्रावास व मृत श्रमिकों के क्षतिपूर्ति के भुगतान आदि में फर्जी तरीके से निगमों पालिकाओं द्वारा बांटा जा रहा है।

(शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com
करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत
साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें
मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है
मो. 9425125569 / 9479535569
ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958